दैनिक जागरण

बृहस्पतिवार, 23 जुलाई 2015 : आषाढ़ शुक्ल 7, वि. 2072

असफलता ही सबसे बड़ी शिक्षक है

बंधक बनी संसद

आखिरकार संसद लगातार दूसरे दिन भी हंगामे का शिकार बनाई गई। राज्यसभा के साथ-साथ लोकसभा में भी कोई कामकाज नहीं हो सका। यह कहना मुश्किल है कि आगे संसद सही तरह चल पाएगी, क्योंकि विपक्ष खासकर कांग्रेस और वामदल अपने अड़ियल रवैये का परित्याग करने के लिए तैयार नहीं दिख रहे। सबसे ज्यादा हमलावर रुख कांग्रेस का है, लेकिन वही बहस से बचने में सबसे आगे भी है। पता नहीं क्यों कांग्रेस के नीति-नियंता यह देखने से इंकार कर रहे हैं कि संसद में तमाशे से उनकी बुरी तरह फजीहत हो रही है। कांग्रेस के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं कि ललित मोदी की कथित तौर पर मदद के मामले में ऐसे किस नियम-कानून का उल्लंघन हुआ है जिसके आधार पर सुषमा स्वराज को विदेश मंत्री पद छोड़ देना चाहिए? उन्होंने तो ब्रिटिश सरकार से केवल यही कहा था कि यदि वह ललित मोदी को ब्रिटेन से बाहर जाने की इजाजत देती है तो इससे दोनों देशों के रिश्तों पर कोई असर नहीं पड़ेगा और ब्रिटिश सरकार इस बारे में अपने नियमों के हिसाब से ही फैसला ले। आखिर इतनी सी बात पर आसमान सिर पर उठाने का क्या मतलब? यदि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों को इस मामले में कोई स्पष्टीकरण चाहिए तो वे बहस से क्यों भाग रहे हैं? गत दिवस कांग्रेस यह कथित तर्क लेकर सामने आई कि एक वक्त खुद भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी ने हवाला कांड में नाम आने के बाद संसद सदस्यता छोड़ दी थी। एक तो हवाला कांड की ललित मोदी प्रकरण से कहीं कोई तुलना नहीं हो सकती और दूसरे कांग्रेस इस तथ्य को छिपा रही है कि आडवाणी ने चार्जशीट में अपना नाम आने के बाद त्यागपत्र दिया था।

अगर कांग्रेस और उसका साथ दे रहे विपक्षी दलों को यह लग रहा है कि वे सही हैं और उनके पास तमाम प्रमाण भी हैं तो वे अदालत की शरण क्यों नहीं लेते? विपक्षी दल ललित मोदी मसले पर हंगामा करने के साथ ही व्यापम घोटाले को लेकर भी सरकार को घेर रहे हैं। निःसंदेह यह एक गंभीर मसला है और उस पर संसद में बहस भी हो सकती है, लेकिन विपक्ष को इसी के साथ अन्य राज्यों के घपले-घोटालों पर भी बहस के लिए तैयार रहना चाहिए। सत्तापक्ष-विपक्ष के लिए अलग-अलग संसदीय नियम नहीं हो सकते। आखिर विपक्ष मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले के साथ-साथ केरल, हिमाचल, असम और गत दिवस ही सामने आए उत्तराखंड के घोटाले पर चर्चा के लिए क्यों नहीं तैयार? व्यापम घोटाले के मामले में इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि सीबीआइ ने उसकी जांच शुरू कर दी है और बहुत संभव है कि सुप्रीम कोर्ट उसकी निगरानी भी करे। स्पष्ट है कि अब इस तर्क के लिए भी कोई गुंजाइश नहीं बची है कि मध्यप्रदेश सरकार जांच प्रभावित कर सकती है। कांग्रेस इस घोटाले की सीबीआइ जांच के बावजूद शिवराज सिंह का इस्तीफा मांग रही है। यदि वह अपनी इस मांग को लेकर सचमुच गंभीर है और कोई नैतिक उदाहरण पेश करना चाह रही है तो फिर उसे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री से तत्काल त्यागपत्र मांग लेना चाहिए। स्पष्ट है कि वह ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि उसकी दिलचस्पी केवल शोर मचाकर खबरों में बने रहने की है। उसकी यह चाहत तो पूरी हो रही है, लेकिन एक जिम्मेदार दल के रूप में उसकी साख रसातल में भी जा रही है।

नहीं सुधरती पुलिस

उत्तर प्रदेश में न्याय मिलना आसान नहीं रह गया है। यहां न्याय की राह में रोड़े ही रोड़े हैं। मामला पुलिस से जुड़ा हो तो कहना ही क्या। यहां तो पीड़ित को रिपोर्ट दर्ज कराने में ही छींकें आ जाती हैं। ऊंची सिफारिश न हो तो थाने में सुनवाई का मतलब ही नहीं। वारदात कितनी ही गंभीर क्यों न हो पुलिस रिपोर्ट दर्ज करने में ही आपकी सारी ऊर्जा नष्ट कर देगी। हाल में आगरा में हुई एक लोमहर्षक घटना का ही उदाहरण लें। वहां एक महिला की बर्बरता पूर्वक हत्या कर चार टुकड़े कर दिए गए। घटना स्थल से पुलिस चौकी महज दो सौ मीटर की दूरी पर थी, लेकिन जब पुलिस को घटना की सूचना मिली तो वह पड़ताल के बजाय मामले को दबाने में जुट गई। घटना को अंजाम देने वाले दबंगों से साठ-गांठ कर पुलिस ने मिट्टी के तेल और चमड़े के टुकड़ों से शव को जलाने की कोशिश की। बाद में जागरण ने पड़ताल कर रिपोर्ट प्रकाशित की तब अधिकारी चेते और डीआइजी के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई। यह एक उदाहरण है। ऐसे और भी उदाहरण हैं। कुछ दिन पहले ही फीरोजाबाद में पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी के पुत्र अमनमणि त्रिपाठी की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई, जिसमें उनकी पत्नी सारा की मौत हो गई और कार चला रहे अमनमणि को खरोंच तक नहीं आई। इस प्रकरण में सारा की मां ने फीरोजाबाद पुलिस पर सहयोग न करने और अन्य तथ्यों को नजरअंदाज करने जैसे गंभीर आरोप लगाए। आखिर अब राज्य सरकार सीबीआइ जांच की सिफारिश करने जा रही है। ऐसे में पुलिस पर तथ्यों को नजरअंदाज करने के लग रहे आरोप सही ही प्रतीत होते हैं।

थानों में पुलिस की कार्यशैली के और भी उदाहरण हैं। इसी माह बाराबंकी में न्याय मांगने थाने पहुंची एक पत्रकार की मां के साथ जो हुआ, वह किसी के लिए भी भयावह स्वप्न की तरह ही होगा। महिला ने पुलिस से अपने निर्दोष पति को छोड़ने की गुजारिश क्या की, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा अपराध कर डाला। पहले महिला के साथ जमकर अभद्रता हुई, फिर दुराचार के प्रयास और जिंदा जलाने की वारदात सामने आई। ये घटनाएं बताती हैं कि पुलिस न तो अतीत से कुछ सीखना चाहती है और न ही उसे अपने मैले दामन की परवाह है। पुलिस तो खैर हमेशा से इन्हीं आरोपों में रही है इसलिए चिंता राज्य सरकार को अपने दामन की करनी चाहिए।

सुधार बनें आंदोलन

सरकार की योजनाओं की सफलता के लिए इनमें लोगों की भागीदारी जरूरी बता रहे हैं डॉ. उदित राज

जब-जब सरकार बदलाव की शुरुआत करती है तब-तब लोगों में आशा और उत्साह पैदा होता है, लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता है, उसकी आलोचना भी शुरू हो जाती है। 2 अक्टूबर, 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की ताकि देश साफ-सुथरा हो जाए। उन्होंने इसे पार्टी से न जोड़ने की अपील की ताकि लोग इस कार्यक्रम को राजनीति से प्रेरित न समझें और दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर इसमें सहयोग दें। प्रधानमंत्री ने स्वयं हाथ में झाड़ू पकड़ी। यह एक अप्रत्याशित बात थी। प्रधानमंत्री को देख लाखों लोग झाड़ू लेकर सड़कों पर उतर गए। शुरुआत में ही एक संदेश गया कि सफाई करना नीच कार्य नहीं है। इसके बावजूद देशवासियों ने इस कार्यक्रम को मन से नहीं अपनाया।

हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में भारतीयों को संबोधित करने का मौका मिला। जब सवाल-जवाब का समय आया तो एक महानुभाव ने कहा कि भारत में अभी भी गंदगी है। मोदीजी ने क्या किया? मैंने उनसे कहा कि आप भारत से आए हैं तो यह भी जानते होंगे कि वहां सैकड़ों विश्वविद्यालय और लाखों स्कूल-कॉलेज हैं। लेखक, पत्रकार, विद्वान और सामाजिक कार्यकर्ता लाखों की संख्या में हैं। ये सब मिलकर छात्रों और देशवासियों को यह छोटा-सा पाठ नहीं पढ़ा सके कि लोगों को स्वच्छ रहना चाहिए। जब शिक्षा का इतना विशाल ढांचा एक छोटी-सी सीख नहीं दे सका तो कमी उसकी है या प्रधानमंत्री की? क्या प्रधानमंत्री को देश को स्वच्छ बनाने की अपील करनी चाहिए थी? अपील इसलिए की क्योंकि देश के विकास में इसकी बड़ी आवश्यकता है। अगर हमारी शिक्षा व्यवस्था ने इस कार्य को किया होता तो सरकार का समय और संसाधन किसी और कार्य में लगते। उन्हें प्रधानमंत्री का धन्यवाद करना चाहिए था बजाय यह कहना कि कुछ नहीं हुआ है।

सरकारी नौकरी सबसे अच्छी है और उसे प्राप्त करने के लिए करोड़ों युवा अपनी जवानी बर्बाद कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और अधिकारियों को समय पर आने और जाने के लिए बायोमैट्रिक व्यवस्था की तो इससे तमाम लोग नाराज हो गए। उन्हें आदत पड़ी थी देर से आने और जल्दी जाने की। नए नियम से उन्हें तकलीफ होनी शुरू हो गई। भाजपा को इसका थोड़ा-बहुत खामियाजा दिल्ली के चुनावों में भी भुगतना पड़ा। एक डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेस मैनेजर जो आराम से बड़ी कंपनियों में लाखों-करोड़ों कमा सकते हैं, क्यों नौकरशाही में घुसने को वरीयता देते हैं। आखिर ऐसा क्यों? समझना मुश्किल नहीं है। सरकारी नौकरी में काम कम करना पड़ता है। देर से आएं और पहले चले जाएं तो भी काम चलता रहता है। तमाम मलाईदार विभागों का लालच तो है ही।

भारत में लोगों की ऐसी मानसिकता बन गई है कि सबकुछ सरकार करे। सवाल यह खड़ा होता है कि सरकार जनता से अलग थोड़े ही है। वह तो लोगों से ही बनती और चलती है। जो प्रतिनिधि होते हैं, वे नेतृत्व कर सकते हैं, लेकिन नियम-कानून मानना और सरकारी घोषणाओं और कार्यक्रमों को लागू करना सभी लोगों पर निर्भर करता है। जनता के हित में सरकार के कुछ कार्यक्रम जैसे- स्वच्छता, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, सांसद आदर्श ग्राम योजना, जनधन योजना, स्किल इंडिया आदि यदि ठीक से लागू हो जाएं तो भारत में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। उसी तरह जैसे दूसरे देशों में समय-समय पर परिवर्तन हुए हैं। बिना लोगों के सहयोग के यह संभव हो नहीं सकता।

देश में चाहे जितने संसाधन, उपयुक्त जलवायु, उर्वरा भूमि हो फिर भी तब तक विकास नहीं होगा जब तक अच्छा समाज बनाने और विकास में योगदान देने के लिए जनता आगे न आए। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भारत की दृष्टि से उतनी अनुकूल स्थिति में नहीं हैं, लेकिन उन्होंने तरक्की के झंडे गाड़ दिए। ऑस्ट्रेलिया में 1770 के आस-पास इंग्लैंड और यूरोप से काला पानी की सजा काटने वाले आए और 200 वर्ष के अंतराल में किस ऊंचाई पर पहुंच गए, जानना मुश्किल नहीं है। कुछ लोग यह कह सकते हैं कि हमारी आबादी की समस्या है तो उसका भी जवाब है कि जापान और कोरिया जैसे ऐसे देश हैं, जहां आबादी का घनत्व भारत से भी ज्यादा है, जमीन भी समतल नहीं है और पहाड़ ही पहाड़ दिखाई पड़ते हैं, फिर भी उन्होंने विकास के नए प्रतिमान स्थापित किए हैं। इससे स्पष्ट है कि देश का निर्माण नागरिक करते हैं।

भारतीय समाज में क्रांति की आवश्यकता है। जिस तरह यूरोप में 14वीं से 17वीं शताब्दी तक नवजागरण के दौरान वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा मिला, उसी प्रकार के नवजागरण की आवश्यकता भारत को भी है। यह नवजागरण इटली से उठा और पूरे यूरोप को अपने आगोश में ले लिया। यूरोप ने दूसरा आंदोलन भी देखा जो 16वीं शताब्दी में उभरा। इसे सुधारवाद के नाम से जाना जाता है। 1860 तक जापान दुनिया के और समाजों से कटा हुआ था और सोचा जा सकता है कि वह तमाम ज्ञान/विज्ञान और तकनीक से वंचित और पिछड़ा रहा होगा, लेकिन मेजी क्रांति ने जापान को बदलकर रख दिया। जापान में वर्ष 1868 और 1872 के बीच उत्पादन 1026 टन और निर्यात 646 था, जो साल 1909 से 1914 के बीच बढ़कर क्रमशः 12,460 और 9,462 टन हो गया। मेजी आंदोलन के पीछे अमेरिकी प्रगति भी थी। जब जापानियों को पता लगा कि अमेरिका कितना आगे है तो उनमें भी जज्बा पैदा हो गया कि हमें जो भी बलिदान करना होगा, करेगें। उस विकास को कौन नही जानता। मेजी का मतलब होता है प्रबुद्ध प्रशासन, जिसमें पूर्वी और पारंपरिक मूल्यों के साथ-साथ आधुनिकता का मिश्रण हो। इसी तरह से चीन में 1966 में सांस्कृतिक क्रांति शुरू हुई। उसने वहां के लोगों की सोच बदलने में बड़ा योगदान दिया। हालांकि इस क्रांति के दौरान सरकार ने जोर-जबर्दस्ती भी की, जिसका बड़ा नकारात्मक असर पड़ा।

यदि सरकारी योजनाओं को कारगर ढंग से लागू कर दिया जाए तो भारत में बड़ा बदलाव आ सकता है। सरकारें कम ही क्रांतिकारी कदम उठाती है, इसलिए यह अभियान सराहनीय है। समाज सुधार की पहल तभी सफल हो सकती है जब इसमें समाज की भागीदारी हो। स्वच्छ भारत अभियान समाज के आह्वान पर शुरू होना चाहिए था, लेकिन किया गया सरकार की ओर से। अगर समाज इस अभियान में भागीदारी कर इसे सफल नहीं बनाता तो यह एक ऐतिहासिक भूल होगी।

(लेखक लोकसभा के सदस्य हैं)

response@jagran.com

सबका साथ

◆ स्वच्छ भारत अभियान समाज के आह्वान पर शुरू होना चाहिए था, लेकिन किया गया सरकार की ओर से। अगर समाज इस अभियान में भागीदारी कर इसे सफल नहीं बनाता तो यह एक ऐतिहासिक भूल होगी

हमारी थाली में जहर

खाद्य पदार्थों में मिलावट पर रोक लगाने के लिए कड़े उपायों की जरूरत बता रहे हैं डॉ. अनिल प्रकाश जोशी

खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के एक सर्वेक्षण से पता चलता है कि भारत में प्रत्येक पांच में से एक खाद्य पदार्थ प्रदूषित है। यह सर्वेक्षण 14 राज्यों में किया गया था। ऐसे ही एक अन्य सर्वेक्षण से खुलासा हुआ कि 5 से 7 प्रतिशत अंडे घातक सालमोनेला बैक्टीरिया से संक्रमित हैं। इसी तरह फलों का डिब्बाबंद जूस बेहद हानिकारक तत्वों से दूषित है जिनसे गंभीर रोग हो सकते हैं। भारत में खाद्य असुरक्षा का स्तर 11.1 प्रतिशत है। जो पाश्चात्य देशों के मुकाबले करीब तीन गुना है। चीन में खाद्य असुरक्षा का स्तर 9.9 प्रतिशत है। फूड सेंट्री कंपनी के सर्वेक्षण के अनुसार दुनिया के 34,000 खाद्य उत्पादों में खाद्य सुरक्षा के नियमों का सबसे ज्यादा 23.5 प्रतिशत उल्लंघन समुद्री उत्पादों में होता है। इसके बाद फल-सब्जी में 20 प्रतिशत, दूध, मसालों और अनाज में सात से नौ प्रतिशत है। चाहे मीट उत्पाद हों या सूखे फल, इनमें कहीं न कहीं खाद्य सुरक्षा के मानकों का उल्लंघन हो रहा है। दुनिया में खाद्य असुरक्षा के बड़े कारकों में 264 तत्वों को चिह्नित किया गया है। इनमें पहली पंक्ति में पेस्टीसाइड और पैथोजन हैं। यही नहीं, खाद्य पदार्थों में उपयोग आने वाले कई तरह के अन्य रसायन भी खाद्य पदार्थों को प्रदूषित बना रहे हैं। अन्य प्रमुख तत्वों में एंटीबायोटिक, टॉक्सिन, मैटल, दवाइयां आदि आती हैं।

मैगी ने एक बार खाद्य सुरक्षा के सवाल सुर्खियों में जरूर ला दिया है, पर यह तो प्रदूषित भोजन श्रृंखला का एक छोटा सा हिस्सा भर है। हमारी रसोई में उपयोग आने वाले प्रत्येक खाद्य उत्पाद किसी न किसी रूप में मिलावटी और प्रदूषित हैं। बड़ी कंपनियों को तो सरलता से कठघरे में खड़ा किया जा सकता है पर सवाल उन सब उत्पादों का है जिनकी जांच ही नहीं की जाती। जिस आटे की रोटी या ब्रेड हम रोजाना उपयोग में लाते हैं उसमें कम से कम 25 विभिन्न रसायनों का उपयोग होता है, जो हमारे लीवर और किडनी के लिए ठीक नहीं हैं। जो फल आप खुद को स्वस्थ रखने के लिए खाते हैं वे अगर इंडोफोन हारमोन्स से पकाए गए हों तो आपके स्वास्थ्य को चौपट कर सकते हैं।

हमारे बड़े फूड स्टोर में जो भी बिकता हो उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। पिछले कुछ अंतरालों में खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने इन स्टोरों में बिकने वाले कई उत्पादों को कठघरे में खड़ा किया है। इनमें हैन्ज, कैलोग, केडबरी, पारले के कई उत्पादों को उनके मानकों के पर खरा नहीं पाया गया है। इनमें असुरक्षित और सीमा से अधिक रसायन पाए गए। इस श्रेणी में ऊर्जा ड्रिंक्स के नाम पर बाजार में उतारे गए उत्पाद क्लाउड 9, मोनेस्टर, जिंगा आदि भी शामिल हैं। इनमें जिनसेंग और कैफिन का अत्यधिक उपयोग किया गया है। अब देखिए शंघाई से लेकर केरल तक इस्तेमाल किए जा रहे चीन में उत्पादित न्यू किड नामक ब्रांड के चावल की गुणवत्ता पर बड़ा प्रश्नचिह्न लगा है।

देश में 1954 के खाद्य मिलावट कानून के अनुसार आठ खाद्य रंगों के उपयोग पर रोक लग चुकी है पर आज भी धड़ल्ले से इनका प्रयोग हो रहा है। सब्जी और मसालों को रंगने के लिए उपयोग में आने वाले रंग शरीर के लिए घातक सिद्ध होते हैं, यह सबको पता है पर इसे रोकने के लिए ठोस प्रयास नहीं किए गए। ऐसे में सवाल उठता है कि हम अपनी थाली में बढ़ते जहर को रोकने में कितने सक्षम हैं। असल में दो बड़े कदम ही खाद्य सुरक्षा में होने वाली अनियमितताओं को रोक सकते हैं। पहला कदम है मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री पर सजा के प्रावधान कड़े करना। वर्तमान में मिलावट में अधिकतम सात साल की जेल या किसी की मृत्यू हो जाने पर जीवन भर जेल और 10 लाख जुर्माने का प्रावधान है। दूसरी परिस्थितियों में कम से कम छह महीने की जेल और एक लाख जुर्माने का प्रावधान है। पर आज तक जुर्माना पाने वाले और जेल जाने वाले कितने लोग हैं, यह बड़ा प्रश्न है। खाद्य पदार्थों में मिलावट के आरोपियों को आसानी से जमानत मिल जाती है। इस प्रावधान को भी कड़ा किया जाना चाहिए।

दूसरा उपाय है खाद्य पदार्थों में मिलावट को पकड़ने की हमारी तैयारी चाक-चौबंद होनी चाहिए। खाद्य सुरक्षा राज्यों का विषय है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात जैसे कुछ राज्य खाद्य सुरक्षा के प्रति सजग नजर आते हैं पर अन्य राज्यों की गंभीरता संदिग्ध है। देश की राजधानी दिल्ली में मात्र 12 फूड इंस्पेक्टर हैं, जबकि तमिलनाडु में इनकी संख्या पांच सौ है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में 430 फूड इंस्पेक्टरों के पद रिक्त हैं। सीधी सी बात है कि सरकारें अभी तक खाद्य सुरक्षा के मुद्दे पर गंभीर नहीं हैं।

दूसरी तरफ ज्यादातर राज्यों में मिलावट की जांच करने वाले लैब भी पूरी तरह सक्षम नहीं हैं। एक बार में ये लैब 10-12 सैंपलों का ही निरीक्षण कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, दिल्ली में 10 कैमिस्ट की जगह तीन ही कैमिस्ट हैं। मैगी की बात तो किसी फिल्म के ट्रेलर से ज्यादा कुछ नहीं है। मुद्दा इससे कहीं बड़ा है। हमारे हर तरह के भोजन में किसी न किसी तरह का जहर मिला है और हम इससे बेखबर हैं। सवाल उन सब पदार्थों का है जो हमारे शरीर को रोगी बना रहे हैं। ध्यान रहे कि हमने खुद ही अपने को मिटाने के रास्ते तैयार कर रखे हैं।

हमारी जीवनशैली इस तरह के उत्पादों को बढ़ावा दे रही है। कुछ ही दशकों पहले सब कुछ अपने ही नजदीक उत्पादित होता था। नई वैश्विक आर्थिकी का एक नकारात्मक पहलू यह भी है कि यह उत्पादन और उपभोक्ता के बीच दूरी बढ़ा देती है। स्वदेशी और स्थानीय उत्पादन निश्चित रूप से बेहतर साबित हो सकते हैं। हमें और सरकारों को यह नहीं भूलना चाहिए कि यह जीवन का सवाल है और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही की अनुमति नहीं दी जा सकती।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

response@jagran.com

प्रदूषित भोजन श्रृंखला

◆ मैगी ने एक बार खाद्य सुरक्षा के सवाल सुर्खियों में जरूर ला दिया है, पर यह तो प्रदूषित भोजन श्रृंखला का एक छोटा सा हिस्सा भर है

ऊर्जा

परम पुरुष

ईश्वर का भजन करके, ईश्वर का सान्निध्य पाकर मनुष्य क्या करेगा? उस समय वह कोई काम करेगा या सेवा करेगा। भगवान की सेवा, परम पुरुष की सेवा। सेवा क्या है? आप जानते है कि दो मनुष्यों का संपर्क यदि लेन-देन के आधार पर हो यानी किसी ने एक रुपया दिया, उससे एक रुपये की वस्तु खरीदी, तो उसे व्यवसाय कहेंगे। यह भक्ति नहीं है। भक्ति होती है एकतरफा। यानी आप चाहते हो, मैं जो भी कर सकूं, भगवान के लिए करूं और उसके विनिमय में कुछ न लूं। अब भगवान मनुष्य के पास से क्या चाहते हैं? वे कुछ भी नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते? कारण यह कि उनके पास कोई भी अभाव नहीं है, तो वे क्या मांगेगे? कुछ भी नहीं। इसलिए इस विचार से देखने पर भगवान को मनुष्य कुछ भी नहीं दे सकता है। जबकि मनुष्य भगवान से बहुत कुछ मांग सकता है- नाम, यश, संपदा। जैसे- किसी व्यक्ति को मैंने 100 रुपये दान में दिए और फिर दानदाताओं की सूची में अपना नाम तलाशना शुरू कर दूं। यह दान एकतरफा नहीं रहा। आपने दान दिया और विनिमय में यश पाने की चेष्टा की।

इसलिए यह आपकी सेवा ही नहीं हुई, दान भी नहीं हुआ। आपने तो सीधे-सीधे व्यवसाय किया है, रुपया दिया है और खरीदा है नाम, यश। इसलिए यह सेवा नहीं हुई। तो भगवान की सेवा किस प्रकार करेंगे। हां, भगवान की सेवा दो पद्धतियों से की जा सकती है। एक पद्धति यह है कि परमपुरुष द्वारा सृष्ट यह जगत है। इस जगत का प्रत्येक जीव जब परम पुरुष द्वारा सृष्ट है, तब प्रत्येक जीव परमपुरुष का अत्यंत प्रिय होगा।

असल में बात यह है कि सभी परम पुरुष के प्रिय हैं, किंतु जो लोग सत्पथ पर हैं, परमपुरुष उनका कम तिरस्कार करते हैं, उन्हें कम डांटते हैं और जो दुष्ट हैं उन्हें डांटते हैं, थोड़ी-बहुत सजा भी देते हैं, किंतु घृणा नहीं कर सकते, प्यार का पात्र वह भी है। इसलिए उस पर कुछ शासन, तिरस्कार करके उसे अच्छा बना देना चाहते हैं। कैसे? जैसे कोई रास्ते से जा रहा है और उसकी पोशाक साफ-सुथरी है, बच्चे की मां उसी अवस्था में उसे गोद में उठा लेती है और जो लड़का रास्ते में गिर पड़ा था और उसके कपड़े धूल से सन गए थे, मां उसके कपड़े झाड़कर उसे गोद में ले लेती है। आशय यह है कि मां को दोनों प्रिय हैं।

◆ श्रीश्री आनंदमूर्ति

जागरण Junction AAPKI AWAAZ, AAPKA BLOG www.jagranjunction.com

काश! मां व्हाट्सएप पर होती

घर से बहुत दूर हूं। लोग मशीनों की तरह काम करते हैं यहां। किसी के पास फुर्सत नहीं एक-दूसरे का दर्द बांटने की। ऐसा लगता है जैसे तरक्की की दौड़ में इंसान ने भावनाओं का गला घोंट दिया है। न जाने क्यों कभी-कभी लगता है कि बहुत अकेला पड़ गया हूं। यूं तो वक्त-बेवक्त घर पर फोन से बात हो जाती है। मार्गदर्शन मिलता रहता है। ये करना, वो मत करना, अपना खयाल रखना वगैरह वगैरह। पहले कम से कम इतना तो था कि हफ्ते या महीने भर में एक बार ही सही पर दोस्त जब हाल-चाल लेने को कॉल किया करते थे तो उनकी आवाज सुन कर सुखद अहसास होता था। अब तो व्हाट्सएप, हाइक, आइएमओ, लाइन, वी चैट और टेलीग्राम जैसी बेहिसाब सोशल नेटवर्किंग साइटों के चलते इंसान उठते-बैठते, चलते-रुकते हर वक्त फोन की स्क्रीन पर नजरें गड़ाए रहता है। दोस्त-यारों से लेकर मेरे ऑफिस का चपरासी तक व्हाट्सएप पर है। सारे के सारे चौबीस घंटे मुझसे जुड़े हुए हैं। बस एक ही कमी जिसके जुड़ने से थोड़ी राहत-सी आ जाती है, वह नहीं है यहां व्हाट्सएप पर। मां नहीं है व्हाट्सएप पर। **-पुनीत मानव**

पूरा ब्लॉग पढ़ने के लिए यथावत टाइप करें : http://bit ly/1LCJMoC

याकूब मेमन की फांसी

मार्च 1993 में मुंबई में एक के बाद एक हुए कई सीरियल धमाके हुए थे। इन धमाकों में 257 लोग मारे गए और 700 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए थे। इस मामले में कई लोगों पर मुकदमे दर्ज हुए, जिनमें दाऊद इब्राहिम और टाइगर मेमन मुख्य थे। मेमन को छोड़कर बाकी 10 दोषियों की फांसी की सजा को उम्रकैद में बदल दिया गया था और अब टाइगर के भाई याकूब को लंबे इंतजार के बाद फांसी के तख्ते पर लटकाने का अंतिम फैसला हो चुका है। 25 सालों में एक पूरी की पूरी पीढ़ी बदल जाती है और इस बदली हुई पीढ़ी को हम भला कैसे समझा पाएंगे कि याकूब मेमन को फांसी क्यों दी जा रही है! चलिए, इनको हम जैसे-तैसे थोड़ा बहुत समझा भी लें या फिर यह पीढ़ी इंटरनेट सर्च से जानकारी जुटा भी ले तो वह 1993 के अपराध की भयावहता को किस प्रकार महसूस कर पाएगी? **-मिथिलेश**

पूरा ब्लॉग पढ़ने के लिए यथावत टाइप करें : http://bit ly/1VtQl1e

नदियों को जोड़ें

'किसानों के लिए नया ख्वाब' लेख में डॉ. भरत झुनझुनवाला ने सही कहा है कि भारतीय कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और इसके विकास से ही किसानों का विकास संभव होगा। भारतीय खेती को भारी नुकसान पहुंचाने वाले दो प्रमुख कारण बाढ़ और सूखा हैं। स्वतंत्रता के इतने साल बाद भी इन आपदाओं से निपटने के लिए जो कुछ भी किया गया है वह नाकाफी है। प्रत्येक वर्ष इन्हीं दो कारणों से बड़े भूभाग में फसल बर्बाद हो जाती है और किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते हैं। मैं वित्तमंत्री से कहना चाहूंगा कि नदियों को आपस में जोड़ने के कार्यक्रम की तरफ ध्यान दिया जाए। इस योजना से बाढ़ और सूखा दोनों पर अंकुश लगेगा।

जियाउल्लाह, आजाद नगर, इटावा

दरिंदगी का हल

दरिंदे रविन्द्र द्वारा 15 मासूमों की दुष्कर्म के बाद नृशंस हत्या और मिनाक्षी के पड़ोसी गुंडों द्वारा सरेआम चाकुओं से गोदकर हत्या की खबरों ने सभी को स्तब्ध कर दिया है। बड़ी अजीब और शर्म की बात तो यह है की ऐसी घटनाएं रुकने का नाम ही नहीं ले रही हैं। असल में आज माता-पिता, शिक्षक, समाज और शासन आदि का किसी को कोई भय नहीं है। ऊपर से अश्लील सिनेमा आदि आग में घी का काम कर रहे हैं। ऐसे दरिंदों को फांसी पर लटकाना ही एक मात्र उपाय है। **वेद मामूरपुर, नरेला**

पाठकनामा

pathaknama@nda.jagran.com

पार्टी का प्रचार

आम आदमी पार्टी द्वारा सरकारी खर्च पर दिए जाने वाले सस्ते भोजन के स्थान का नाम तथा गली मोहल्ले में खोले जाने वाले छोटे -छोटे अस्पताल का नाम अपनी राजनीतिक पार्टी के नाम पर रखना कतई उचित नहीं है। एक तरह से यह अपनी राजनीतिक संस्था का सरकारी खर्च पर प्रचार जैसा है, जो गैर कानूनी भी है। दिल्ली में ही जब शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थीं तो उन्होंने भरपेट भोजन जिसकी शुरुआत कम मूल्यों पर की थी उसका नाम जन आहार रखा था, न कि कांग्रेस भोजनालय। आम आदमी पार्टी सरकार को भी इस योजना का ऐसा ही कुछ नाम रखना चाहिए।

amodforjustice@gmail.com

कांवड़ मार्ग की दुर्दशा

पश्चिम यूपी के कद्दावर जाट नेता और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के नाम से बना मात्र 60 किमी लम्बा कांवड़ मार्ग आज अपने उद्धार की राह ताक रहा है। विडंबना देखिये कि इस मार्ग के दोनों ओर बसे गांव अधिकांशतः जाट बहुल ही हैं, लेकिन दिवंगत नेता के पुत्र ने कई बार केंद्रीय मंत्री बनने के बाद भी इसकी सुध नहीं ली और पोते को क्या मतलब? करीब एक हफ्ते चलने वाली कांवड़ यात्रा में कांवड़िये स्थानीय न होकर अन्य क्षेत्रों से आते हैं जिनके वोट से स्थानीय नेताओं को कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए नेताओं को कांवड़ मार्ग की दुर्दशा से कोई लेना देना नहीं।

rachnarastogi66@gmail.com

नरमी नहीं, प्रहार

पूरा विश्व आतंक की चपेट में है, समय -समय पर आतंकवादी संगठन निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतारते रहते हैं। ये वो लोग हैं जो आतंक का सहारा लेकर दुनिया में इस्लाम का झंडा बुलन्द करना चाहते हैं। ये धार्मिक दिवालियेपन के शिकार हैं। जिन्हें धर्म के बारे में कोई जानकारी है ही नहीं। क्या इस्लाम खून खराबे को जायज ठहराता है? क्या इस्लाम धार्मिक कट्टरपन को अन्य पर थोपना चाहता है? इस्लाम तो शांति का मानवता का सन्देश देता है पर कुछ भटके लोग सीधे -साधे लोगों को बरगलाकर उनसे निर्दोषों का खून करवाते हैं। आतंक किसी भी रूप में हो उसके साथ नरमी नहीं, प्रहार होना चाहिए। **सुनील प्रेमी, सूरजपुर, ग्रेटर नोएडा**

पुलिस पर हमले

आम जनता की सुरक्षा करने का कार्यभार पुलिस के कंधों पर है, पर बदलते वक्त में पुलिस खुद ही सुरक्षित नहीं है। आए दिन पुलिस पर हमले हो रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे पुलिस का खौफ ही खत्म हो गया है। इसका कारण कहीं न कहीं पुलिस खुद भी है। आज लोगों के दिल में पुलिस की अच्छी छवि नहीं रह गई है। तमाम आपराधिक मामलों में पुलिस की संलिप्तता सामने आती रहती है। अवैध उगाही आम बात है। इन सबसे पुलिस की छवि खराब हुई है। लोगों को पुलिस का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वह आम लोगों की सुरक्षा के लिए ही है। परंतु पुलिस को भी अपने दायित्वों का ईमानदारी से पालन करना चाहिए।

दीप्ति मिश्रा, खोड़ा, नोएडा

जनपथ

चुनकर भेजा है जिन्हें वो करते हुड़दंग,
इनके कारण तंग है राजनीति का रंग।
राजनीति का रंग-ढंग हो गया निराला,
संसद में जा लोग कर रहे गड़बड़झाला।
जनता है हैरान स्वयं अपना सिर धुनकर,
लखि उनका हुड़दंग जिन्हें भेजा है चुनकर।

ओमप्रकाश तिवारी

ट्वीट ट्वीट

अरुण जेटलीजी, कार्यवाही में बाधा डालने की संसदीय परंपरा हमने आपसे ही सीखी है। क्या आपने हमें नहीं बताया था कि यह पूरी तरह संवैधानिक है? इसलिए अब शिकायत कैसी? मुसकुराइए और झेलिए।

दिग्विजय सिंह @digvijaya_28

दिल्ली हारने के बाद से ही बीजेपी बौखलाई हुई है। गंदी राजनीति के तरह-तरह के उदाहरण देखने को मिल रहे हैं। क्या यही गुजरात मॉडल है?

मनोज सुनिया @AAPKaMannu

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या आपको लगता है कि लोढ़ा समिति की रिपोर्ट के मामले में बीसीसीआइ का रवैया टालमटोल वाला है?

आज का सवाल

क्या संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने के लिए नियमों को कड़ा करने की जरुरत है?

अपनी राय और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर POLL लिखें, स्पेस देकर Y, N या C लिखकर 57272 पर भेजें
Y-हां, N-नहीं, C-कह नहीं सकते

परिणाम एसएमएस से प्राप्त नतीजों के साथ जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।